

RNI No. MPHIN/2001/6979

सत्य

नवम्बर-2017

अंतरंग

आ वा ज

(सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक मासिक पत्रिका)

प्रधान संपादक

अभय नारायण श्रीवास्तव

संपादक

कल्पना श्रीवास्तव

कार्यकारी संपादक

रोहित श्रीवास्तव इंजीनियर

प्रबंध संपादक

उदय श्रीवास्तव

उप संपादक

आचार्य अशोक शर्मा भारद्वाज
मंजुला चौधरी खंडवा

संपादकीय कार्यालय :-

एफ-110/8, शिवाजी नगर, भोपाल

मोबाइल : 8959312347

Email : satyaawaz@gmail.com

सत्यनारायण श्रीवास्तव स्मृति
मंच का प्रकाशन



शिवराज की अगुआई में प्रदेश बना अब्बल

-----अंदर पृष्ठों में विशेष-----



मुख्यमंत्री पद की
मिसाल हैं श्री
शिवराज सिंह चौहान-
अंतर सिंह आर्य

स्मार्ट मध्यप्रदेश

के सहज
मुख्यमंत्री
शिवराज
-माया सिंह

स्वामी-कल्पना श्रीवास्तव की ओर से सत्य आफसेट से मुद्रित करवाकर, 110/8, शिवाजी नगर, भोपाल से प्रकाशित।

किसी भी विवाद के लिए न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा। रचनाओं से सहमत होना संपादकीय विभाग की अनिवार्यता नहीं है। संपादक-कल्पना श्रीवास्तव

मासिक पत्रिका

सत्य आवाज

नवम्बर-2017 ♦ 1

संपादकीय

शिवराज की जनकल्याणकारी योजनाएं

इस 29 नवम्बर को मध्यप्रदेश के इतिहास में एक रिकार्ड दर्ज हो रहा है श्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में भाजपा के एक नेता प्रदेश में सबसे ज्यादा समयतक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उनके कार्यकाल के बारह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अपने कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं दी हैं प्रदेश सरकार की योजनाओं से अंतिम छोर का व्यक्ति भी लाभांवित हो रहा है। मातृशक्ति के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाएं बनाई हैं लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है बेटी के जन्म लेते ही उनके मातापिता को सरकार धनराशि उपलब्ध करा रही है तो पढ़ाई पर भी शासकीय मद से राशि खर्च की जा रही है।

प्रदेश के अधिकांश वृद्धजन तीर्थयात्रा के लिए जाना चाहते थे लेकिन लेकिन न उन्हें कोई ले जाने वाला होता था और उन्हें न ही पर्याप्त राशि मिल पाती थी अब यह बीड़ा भी राज्य शासन ने उठाया और वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन कराये जा रहे हैं युवा पीढ़ी विशेषकर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ साथ पढ़ाई और कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिससे गरीब तबके के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अपना भविष्य बना रहे उन्हें पढ़ाई के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया जा चुका है मुख्यमंत्री चौहान ने सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई कार्यक्रम चलाकर जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर प्रयास किया है प्रदेश में किसानों के लिए भी अनेकों निर्णय लिए गये हैं भावांतर योजना ने भी किसानों की समस्या को खत्म किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई और बनाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण जहां प्रदेश की जनता का शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास बढ़ता चला जा रहा है वही मध्यप्रदेश प्रगति और विकास की ओर बढ़ रहा है।

—कल्पना श्रीवास्तव

शिवराज की अगुआई में प्रदेश बना अब्बल



कुछ साल पहले तक बीमारू प्रदेशों की कतार में शुमार किये जाने वाले मध्यप्रदेश की पहचान अब तेजी से विकास करने वाले प्रदेश के रूप में होती है। यह अब कई क्षेत्रों में देश में अगुआ और अब्बल भी बन गया है।

एक दशक में हुए इस चमत्कार के पीछे प्रदेश की तरक्की के प्रति श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प और समर्पण है। उन्होंने शुरू में ही जनता के बीच इस रूप में यह जाहिर कर दिया था कि मध्यप्रदेश उनका मंदिर है, जिसमें रहने वाली साढ़े सात करोड़ जनता उनकी भगवान है और उसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्यप्रदेश को देश का नम्बर एक राज्य बनाऊँगा। इन दोनों बातों की गंभीरता को उस समय लोगों ने भले ही कम समझा हो, लेकिन आज जब यह सब चरितार्थ होते दिख रहा है, तब लोगों में उनके प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हुआ है। प्रदेश में हुए अद्भुत कामों की गूँज न केवल देश में बल्कि दूर देशों तक सुनाई दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख से निकली इन मासिक पत्रिका

सत्य आवाज

दोनों बातों में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का ताना-बाना बुना है। एक दशक से प्रदेश का नेतृत्व करने वाले श्री चौहान को आज भी जनता अपने सबसे नजदीक पाती है तो उनकी सादगी, विनम्रता और सहजता है। यही गुण उन्हें औरों से अलग करते हैं। सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान परिवार में जन्में श्री चौहान को किसी भी प्रकार का बनावटीपन और अहम दूर-दूर तक छू नहीं सका है। उन्होंने जो कहा वो किया। जनता की सुख-समृद्धि के लिये ठोस कार्यक्रम बनाये और उन्हें जमीन पर उतारा भी। उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हर वर्ग के उत्थान की योजनाएँ बनायी तथा प्रदेश के ढाँचागत विकास को प्राथमिकता दी। प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने के लिये खेती को लाभकारी धंधा बनाने का संकल्प लिया। इस दिशा में उन्होंने कृषि की लागत को कम और पैदावार को वाजिब दाम दिलवाने के ठोस कदम उठाये। देश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने और मूलधन की वसूली दस

नवम्बर-2017 ♦ 3



फीसदी कम करने वाला एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश है। इससे कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई। प्रदेश को लगातार चार बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रदेश, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिये स्थानीय निकायों में पचास फीसदी आरक्षण देने में भी अग्रणी है। वैसे तो बेटियों के जन्म से लेकर पोषण, शिक्षा, विवाह, रोजगार आदि का पूरा इंतजाम किया है। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के जीवन को सुखमय बनाने के लिये उन्होंने कामगारों, रिक्शा और हाथठेला चालकों, तुलावटी, हम्माल, शहरी घरेलू काम-काजी महिलाओं आदि निर्धन वर्ग के कल्याण तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम लागू किये हैं।

श्री चौहान की विकास एवं जनोन्मुखी सोच, संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत प्रदेश में सिंचाई, सड़क एवं बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई है। वर्ष 2003 में प्रदेश जहाँ अत्यंत पिछड़ा राज्य था, वहीं आज देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल है तो इस दौरान किये गये कार्य ही हैं। उस समय विद्युत उत्पादन मात्र 5173 मेगावॉट था, आज 16 हजार 116 मेगावॉट हो गया है। सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हो गया है। गेहूँ का उत्पादन मात्र 73.65 मीट्रिक टन था, जो आज 184.80 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2003 में सकल घरेलू उत्पाद 1,02,839 करोड़ था जो आज बढ़कर 5,08,006 करोड़ हो

मासिक पत्रिका

सत्य आवाज

गया है।

श्री चौहान के चमत्कारिक नेतृत्व में मध्यप्रदेश आज देश में विभिन्न क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। चाहे कृषि विकास दर हो, जैविक खेती का क्षेत्र हो, दलहन उत्पादन, सोयाबीन, तिलहन, प्रमाणित बीज, चना, औषधि एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन, लहसुन, अमरूद और मटर उत्पादन, पीपीपी मॉडल में स्टील सायलो की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन व्यवस्था, खेती के लिये प्रतिदिन 10 घण्टे गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदाय में प्रथम है।

इसी तरह पीपीपी मोड में देश में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण, दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन और ई-स्टॉम्पिंग, सबसे ज्यादा तीन शहरों का स्मार्ट सिटी का चयन, निश्चिंत विवाह प्रोत्साहन योजना लागू करने, बहु-विकलांग एवं मानसिक रूप से निश्चिंत व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने की योजना प्रारंभ करने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना लागू करने, लोक सेवा गारण्टी कानून बनाने, सीएम हेल्प लाइन जैसा कॉल सेन्टर प्रारंभ करने आदि क्षेत्रों में भी अव्वल है।

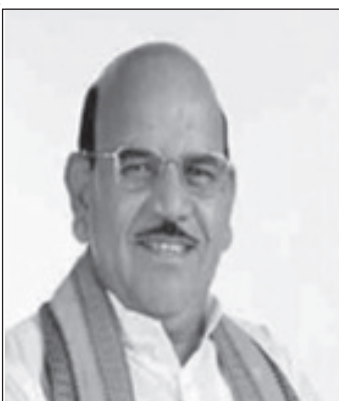
श्री चौहान की अगुआई में मध्यप्रदेश की चहुँदिसा तरक्की की इबारत लिखी जा रही है। इससे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल रही है।

मुख्यमंत्री पद की मिसाल हैं श्री शिवराज सिंह चौहान-अंतर सिंह आर्य



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मैं जब-जब मिला एक बात हमेशा मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। वह थी उनका कमजोर तबके और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा-शक्ति। यह विचारधारा तब और पुष्ट हुई जब मैंने श्रम-अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण पशुपालन मछली पालन कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री का काम सम्हाला। मुख्यमंत्री इन विभागों की चर्चाओं और बैठकों में काफी संवेदनशील हो जाया करते थे।

शायद यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में आज तीर्थ-दर्शन योजना के माध्यम से किसी बुजुर्ग को अपना बेटा दिखता है युवाओं के लिए पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की विभिन्न योजनाओं के कारण युवा वर्ग इन्हें अपना मामा मानते हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों ने



महिलाओं के हृदय में इन्हें भाई का मजबूत ओहदा दिया है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी श्री चौहान गरीब-बेसहारा कन्याओं का विवाह करवाते थे। सीमित संसाधनों के कारण उस समय उनकी हर गरीब कन्या का विवाह कराने की इच्छा हर बार सफल नहीं पाती थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिये मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ला?ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की।

मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि बेटियों के बारे में सदियों से अमरबेल की तरह गहरी ज? जमाई कुरीतियाँ कैसे बदलती है। कन्या जन्म अब माँ-बाप के माथे पर चिंता की रेखाएँ नहीं खुशियाँ लेकर आता है। ला?ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका साक्षात् प्रमाण हैं। आज जहाँ लाखों गरीब माता-पिता की कन्याओं के हाथ सरकार की सहायता से पीले हो गए हैं



और वे अपना सुखी जीवन जी रही हैं वहीं लगभग 26 लाख कन्याओं को ला?ली लक्ष्मी योजना का भरपूर लाभ मिला है। इसलिये गरीब माँ.बाप मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते नहीं थकते हैं।

महिलाओं पर अत्याचार और अपराध रोकने में मुख्यमंत्री ने न केवल पहल की है बल्कि केबिनेट में 12 साल या उससे कम उम्र की ल?कियों से रेप अथवा गैंगरेप के आरोपी को फाँसी की सजा का कानूनी प्रावधान तय करने का निर्णय लिया। यह देश में पहली बार हो रहा है। उम्मीद है जिस तरह से ला?ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान निकाहध्ववाह योजना का अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया है वैसे ही यह प्रावधान भी दूसरे राज्यों के लिये मिसाल बनेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत और स्थानीय निकायों एवं संविदा शाला शिक्षक पदों पर भी 50 प्रतिशत आरक्षण देकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया है।

किसानों के हित में भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गये हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई करने वाली भावांतर योजना भी दूसरे राज्यों के लिए अध्ययन का विषय बन रही है। वर्ष 2003 में किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दिये जाते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्याज दरों को लगातार

घटाते हुए शून्य प्रतिशत कर दिया। सिंचाई रकबे में लाखों हेक्टेयर वृद्धि होने से सिंचाई रकबा ब? और कृषि लाभ का धंधा बनी है। प्रदेश ने लगातार 5 कृषि कर्मण अवार्ड जीते। श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतिहर मजदूरों की कमजोर सामाजिक और आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना शुरू कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी लाभान्वित किया है। गेहूँ, धान, प्याज के समर्थन मूल्य व बोनस घोषित हुए। किसानों को सस्ती और भरपूर बिजली दी जा रही है। अनुसूचित जाति.जनजाति के किसानों को विशेष लाभ दिए गये हैं। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना लागू की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पशुपालन और मछलीपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व.रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर काट्रेक्टर योजना आदि और युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए राज्य कौशल मिशन की सहायता से युवाओं को रोजगार देने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

आम लोगों को लोक सेवाएँ मिलने में कोई कठिनाई नहीं होए इसके लिए मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम



इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को वांछित गति मिली है। प्रदेश में गरीबों को एक रुपये किलो में गेहूँ, चावल और नमक मिल रहा है। होशंगाबाद जिले के गाँव बावा?या की रहने वाली श्रीमती विद्या तंवर और गेंदाबाई कहती हैं कि पेट की चिंता न होने से हम अपना पैसा दूसरे कामों में खर्च करने लगे हैं। इससे हमको सुकून भी मिला है और जीवन में उम्मीदें भी ब?ने लगी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की सबसे ब?ी विशेषता यह है कि वे 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी एक प्रशासक के रूप में लोगों के बीच नहीं लाते। लोग आज भी उन्हें अपने परिवार का भाई, बेटा, मामा और अपने बीच

का ही समझते हैं। इसीलिए समस्या होने पर उनसे गुहार करने में नहीं सकुचाते। श्री चौहान ने महिलाएँ, हम्मालएँ, कामकाजी महिलाएँ, किसानएँ, मछुआ को अपनेपन का एहसास कराया है। उन्होंने उस मिथक को तो? है जो पहले एक मुख्यमंत्री और आम जनता के बीच हुआ करता था।

लागू किया है। आम जनता से जु? विभागों की 164 सेवाओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। जन.शिकायतों के निवारण के लिए श्री चौहान ने सीएनएमए हेल्पलाइन 161 के रूप में अभिनव पहल की है। यह कॉल.सेंटर रोज सुबह 7 से रात 11 बजे तक काम करता है।

मैंने हमेशा देखा कि मुख्यमंत्री गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति चिंतित रहते हैं। उनके दखल के कारण ही प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में आज राज्य बीमारी सहायता योजनाएँ, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजनाएँ, बाल स्वास्थ्य योजनाएँ, निरुशुल्क डायलिसिस, कीमोथैरेपी की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हो पाई हैं। अब



आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग न केवल महंगा इलाज करवा पा रहे हैं, बल्कि बहुत ब?ी संख्या में लोगों को निरुशुल्क दवाइयाँ भी मिल रही हैं।

आज गाँव-गाँव तक स?कों की पुख्ता व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री का मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का सपना एक सार्थक मुकाम तय कर चुका है। इसकी ज? में है गरीबों का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण और कमजोर तबकों का विकास। मुख्यमंत्री अपने लक्ष्य को एक दिन अवश्य हासिल करेंगे क्योंकि उनके ?हन में हमेशा कमजोर वर्गों की तरक्की और विकास के लिए मंथन चलता रहता है।

वे मानते हैं गरीब का उत्थान

प्रदेश का उत्थान है और मुख्यमंत्री रहते हुए वे अपने इस सपने को बेहतर ढंग से सच कर

सकते हैं।

स्मार्ट मध्यप्रदेश के सहज मुख्यमंत्री शिवराज-माया सिंह



प्रदेश में लगातार भाजपा का विजयी झंडा लहराने वाले 12 वर्षों से निरंतर सत्ता के शीर्ष में रहने वाले मुख्यमंत्री एक सहज शालीन और मौन क्रान्तिकारी नेता हैं। श्री चौहान की इन सफलताओं का आधार उनका करिश्माई व्यक्तित्व है जो हर नफरत करने वाले के दिल में भी स्नेह और अपनापन भर देता है।

मुख्यमंत्रित्व काल के बारह वर्ष पूरे करने पर श्री शिवराज सिंह चौहान को हार्दिक बधाई। प्रदेश में लगातार भाजपा का विजयी झंडा लहराने वाले 12 वर्षों से निरंतर सत्ता के शीर्ष में रहने वाले मुख्यमंत्री एक सहज शालीन और मौन क्रान्तिकारी नेता हैं। श्री चौहान की इन सफलताओं का आधार उनका करिश्माई व्यक्तित्व है जो हर नफरत करने वाले के दिल में भी स्नेह और अपनापन भर देता है। पिछले 12 वर्षों में विकास को एक नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनेकों नवाचार और प्रयोग किए हैं जिसे पूरे देश ने माना है। विकास के नए आयाम रचने और मध्यप्रदेश की ब्राँ?ग से उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में तस्वीर बदल दी है।

शिवराज जी के कार्यकाल में प्रदेश बीमारू की इमेज से

उभर कर विकासशील राज्य की श्रेणी में ख ?ा हुआ है। पर्यटन क्षेत्र हो या कृषि लगातार जो अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं वो ना सिर्फ सराहनीय हैं बल्कि भविष्य में इसे बरकरार रखने की चुनौती भी है। हर वर्ग के लिए चिन्तित श्री शिवराज सिंह ने जहां किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की है वहीं छात्र, छात्राओं के लिये के मेधावी योजना भी शुरू की है। वे जितने सहज और शालीन हैं उतने ही कड़े प्रशासक भी हैं।

मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व का सशस्त्र पहलू व्यापक विचारधारा है। आम आदमी के जीवन में आनंद का प्रतिशत ब ?ने की चिंता बच्चों की शिक्षा महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा गाँव शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने का प्रयास बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की चिंता हर

तरह की छोटी-छोटी सुविधाओं और खुशियों का ध्यान एक मुख्यमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने बखूबी किया है।

सेवाएँ समर्पण और सुशासन को समर्पित इन बारह सालों में कोई भी वर्ग शेष नहीं है जिसका कल्याण न हुआ हो। महज 8 से 9 वर्ष की उम्र में ग्रामीण मजदूरों के हित में पहली रैली निकाल कर नर्मदा तट पर दो गुना मजदूरी मिलने तक काम बंद करो का नारा देने वाले आज के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बचपन से ही हर वर्ग के हितों और समस्याओं के लिए

करते। एक सेवक के रूप में गाँवों के खेतों में जाकर अपनी बात रखते हैं। गरीबों के बीच बैठकर उनके साथ भोजन कर अपनी सहजता का परिचय देते हैं।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की प्रगति के लिये कृषि, औद्योगिकीकरण, स्व.रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं। उद्योगपतियों के लिए मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। शिवराज जी युवाओं से कहते हैं कि वे स्व.रोजगार स्थापित कर दूसरों को रोजगार



ख ? हुए हैं। गाँवों में सामाजिक क्रांति लाने में शिवराज सिंह चौहान के प्रयास और प्रशंसनीय नेतृत्व अत्यंत सराहनीय रहे हैं जो अनेक राज्यों एवं केन्द्र के लिए अनुकरणीय बने। गाँव की बेटी योजना, जननी सुरक्षा एवं प्रसव योजना, उषा किरण, तेजस्विनी, वन स्टॉप सेन्टर, ला ? अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान, विवाह योजना, छात्राओं के लिए मुफ्त पुस्तकें, साइकिल, विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और नगरीय निकाय में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन काम किए हैं।

आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं जो भले ही प्रदेश के मुखिया हों परंतु जमीन पर जाकर काम करने में कभी परहेज नहीं

उपलब्ध कराएं। इस प्रदेश से भी टाटा और अंबानी निकलें। सरकार हमेशा इन युवाओं को स्थापित करने में मददगार रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन ने मध्यप्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। आज की स्थिति में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिशन के क्रियान्वयन ने जन.आंदोलन का रूप ले लिया है। लोग अपनी बस्ती, ग्राम, शहर और जिले को शौच मुक्त बनाने के लिए नित नये नवाचार कर रहे हैं।

कुल मिलाकर इन बारह वर्ष में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के विकास की एक नई तस्वीर ग ?ी है। अब प्रत्येक प्रदेशवासी गर्व से कह सकता है कि हम मध्यप्रदेश के हैं जहां बिजली, खेती, किसान, शिक्षा का देश में सम्मान है।

शिवराज ही होंगे भाजपा का चुनावी चेहरा



जिन रामलला का सहारा लेकर देश और राज्यों में भाजपा सत्ता तक पहुंची उन्हीं भगवान श्रीराम की तपभूमि चित्रकूट से कांग्रेस के पक्ष में जयश्री राम हो गया है। लगातार तीसरे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और चित्रकूट से 14333 मतों से सत्तास्व दल भाजपा की पराजय कई मायने रखती है।

चित्रकूट हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है यह 14 वर्ष में कांग्रेस की सबसे बड़ी और उपचुनाव में लगातार दूसरी जीत है। चित्रकूट उपचुनाव के नतीजे ने भाजपा को चिंता है दिल्ली से भोपाल इस परिणाम पर मंथन हो रहा है। साल भर बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसके पश्चात लोकसभा चुनाव होने है इसके पहले प्रदेश में विधानसभा दो चुनाव भी होंगे इन सभी चुनाव में भाजपा के प्रमुख चेहरा शिवराज सिंह चौहान

ही रहेंगे भाजपा उनके नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरेगी क्योंकि प्रदेश में भाजपा कांग्रेस समेत अन्य राजनैतिक दलों में

मध्यप्रदेश की राजनैतिक डायरी -अभय नारायण श्रीवास्तव

ऐसा कोई नेता नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान जितना लोकप्रिय हो और जनता में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव अभियान में बागडोर संभली और पार्टी उम्मीदवारों ने जीत दिलाई है।

भाजपा शासनकाल के 14 वर्ष एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जश्न मनाने जा रही है इसी दिन भाजपा का चुनाव अभियान भी शुरू हो जायेगा, कार्यकर्ताओं को महत्व

देते हुए उन्हें चुनाव में भाजपा को विजय श्री दिलाने का संकल्प दिलाया जायेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव अभियान की बागडोर संभालेंगे। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें मैदान में सक्रिय किये जाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। भाजपा शिवराजसिंह चौहान को ही आगे रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी।

मंत्रिमण्डल विस्तार- विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पश्चात राज्य मंत्रिमण्डल का विस्तार संभव है इस वर्ष में यदि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो ठीक है अन्यथा नये वर्ष में विधानसभा चुनाव होने के कारण विस्तार नहीं हो पायेगा क्योंकि जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जायेगा वे नाराज हो जायेंगे जिससे पार्टी जनों में असंतोष बढ़ेगा। इसी के साथ मंत्रियों के जिला प्रभार भी बदले जाने पर चर्चा चल रही है। इसी तरह निगम मंडल और आयोगों में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों पदों पर भी नियुक्तियों की जा सकती है जिससे उन नेताओं को मौका दिया जायेगा जिनका उपयोग विधानसभा चुनाव प्रभारी अभियान में किया जा सकेगा।

सिंधिया के लिए चुनौती

दिसम्बर में शिवपुरी के कोलारस ओर अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने है दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के



प्रभाव वाले क्षेत्र है कोलारस मुंगावली विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र में है जहां से सिंधिया सांसद है।

कोलारस मुंगावली विधानसभा उप चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

कमलनाथ-सिंधिया की लड़ाई का तीसरे को मिलेगा फायदा

साल भर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा चल रही है कांग्रेस

तक प्रदेशाध्यक्ष बने रहेंगे।

कांग्रेस की चुनावी रणनीति

चित्रकूट चुनाव नतीजे पक्ष में आने के बाद कांग्रेसजनों में उत्साह है अलाकमान ने विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है गुटबाजी समाप्त करने के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं को एक समान महत्व दिया जा सके इसके लिए सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी डाली जा रही है वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जा ही है वही चुनाव की रणनीति बनायेंगे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे तथा



चौहान के लिए भी चुनौतीपूर्ण ही होंगे। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में जिस जीत में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जीत का श्रेय भी राहुल भैया को मिलता है। वही कोलारस और मुंगावली विधानसभा उप चुनाव भी सिंधिया की अगुवाई में ही कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंधिया की पसंद के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं।

के संगठनात्मक चुनाव भी घोषित हो चुके हैं कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए मुहिम छिड़ी हुई है कांग्रेस हाईकमान भी इस संबंध में निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कमलनाथ या सिंधिया में से किसे प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाये ऐसी स्थिति में किसी तीसरे नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है या फिर अरूण यादव विधानसभा चुनाव

उम्मीदवार चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

बाबरिया की क्लास

प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने लगातार 5 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर कांग्रेस जनों की क्लास ली है। उन्होंने विधानसभा चुनाव की रणनीति की बनाई है कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खत्म करने की चेतावनी भी दी है।

युवाओं को रोजगार के लिये तेजी से काम करती मध्यप्रदेश सरकार



मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिये विभिन्न क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य की योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिये उन्हें कौशल युक्त बनाने और उद्योग, व्यवसाय क्षेत्र का विकास कर रोजगार सुलभ कराने की योजनाओं पर भी प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है।

स्किल इंडिया

वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 225 शासकीय एवं 703 निजी आईटीआई संचालित हैं जिनमें प्रवेश की क्षमता क्रमशः 49 हजार और एक लाख 15 हजार सीट है। इन संस्थानों में एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

आईटीआई में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण तथा शिल्पकार ट्रेनिंग योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की 36 आईटीआई में विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007 से कुल

119 करोड़ रुपये के अनुदान से मशीन औजार एवं उपकरण का उन्नयन किया गया है। केंद्र सरकार के प्रति आईटीआई रुपये ढाई करोड़ के ब्याज रहित ऋण से 74 आईटीआई में इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी द्वारा निर्माण कार्य एवं उपकरण एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता का कार्य किया जा रहा है।

समाज के सभी वर्गों के कौशल विकास के लिये एकलव्य एवं डॉण् अम्बेडकर योजना संचालित है। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्राथमिकता से प्रशिक्षित किया जाता है। केवल महिलाओं के लिए 14 महिला आईटीआई संचालित हैं।

कौशल विकास का सर्वव्यापीकरण

प्रदेश में कौशल विकास के सर्वव्यापीकरण के लिये एडीबी से लगभग 1500 करोड़ रुपये, 2940 मिलियन डालर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

इसमें भोपाल में वर्ल्ड क्लास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रमुख है जिसमें उद्यमिता विकास तथा प्लेसमेंट सेल शामिल है। इसके अलावा संभाग स्तर की संस्थाओं का स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थाओं में उन्नयन और अन्य संस्थाओं में अधोसंरचना का विकास करना है। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एवं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी की साझेदारी से प्रदेश को कौशल विकास के क्षेत्र में क्षमतावर्धन हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश में अल्प अवधि के कौशल विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद गठित की गई है। परिषद राज्य कौशल विकास मिशन के रूप में कार्यरत है। परिषद प्रदेश में 135 शासकीय कौशल विकास केन्द्र संचालित कर रही है। इन केन्द्रों में अल्पावधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों द्वारा लगभग



70 हजार युवक.युवतियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एमपीएसीपीएचएचटीएन द्वारा केन्द्र सरकार की मॉड्यूलर एम्प्लायबल स्किल योजना में लाखों प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश में 5ए000 निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को रिकगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम में मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया जा चुका है। कौशल विकास में उद्योगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मारुतिए टोयोटाए डी.ऑटोए एम.आएप्सए साना किचन इत्यादि से प्लेक्सी एमओयू किये गये हैं।

लेबर मार्किट इन्फर्मेशन सिस्टम का विकास करने के लिये प्रदेश में सर्वेक्षण किया जा चुका है। केंद्रीय स्तर पर निर्मित नेशनल केरियर सर्विस पोर्टल की टीम के साथ प्रदेश स्तरीय सिस्टम की चर्चा प्रारंभ की जा चुकी है। सभी आईटीआई में प्लेसमेंट सेल की स्थापना कर प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। आईएचटीआईएच एवं अन्य कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षित युवाओं एवं युवतियों को स्व.रोजगार एवं उद्योग से जु ?ने के लिये इन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कौशल विकास योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना में पचास हजार युवक.युवतियों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि

प्रतिवर्ष सा ? सात लाख युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार या स्व.रोजगार में स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। कौशल और स्व.रोजगार को जो ?ते हुए प्रदेश के युवाओं के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन चलाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के युवक.युवतियों के लिये रोजगार एवं स्व.रोजगार के अवसर ब ?ने के लिये लघु अवधि प्रशिक्षण देने की दो महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुमुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजनाश् और शुमुख्यमंत्री कौशल्या योजनाश् प्रारम्भ की गई है। इन योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अभी तक छह लाख से ज्यादा युवक.युवतियाँ ऑनलाईन पंजीयन के माध्यम से अपनी इच्छा प्रदर्शित कर चुके हैं। दोनों योजनाओं में प्रतिवर्ष सा ? चार लाख युवक.युवतियों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभिन्न सेक्टर्स में प्रशिक्षित किया जायेगा।

स्टार्ट अप इंडिया

भारत सरकार ने जनवरी से स्टार्ट.अप एक्शन प्लान घोषित कर स्टार्ट.अप के लिए अनेक सुविधाएँ घोषित की हैं। साथ ही इन्क्यूबेशन सेन्टर्स स्थापित करने के लिए भी योजनाएँ घोषित की गई हैं। मध्यप्रदेश ने भी अपनी इन्क्यूबेशन और स्टार्ट.अप नीति 2016 बनाकर लागू कर दी है।

लेदर सेक्टर कौशल विकास केन्द्र की स्थापना शिवपुरीए कटनीए ग्वालियरए इन्दौर

और जबलपुर में की गई है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा देवास में इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की गई है। वस्त्र उद्योग के लिए ग्वालियर में इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। ग्वालियर में ही सीपेट का वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर शुरू हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत वाणिज्यए उद्योग एवं रोजगार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन तीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स प्रदेश में संचालित हैं।

स्टेण्ड.अप इंडिया

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ स्टेण्ड.अप इंडिया योजना में हर बैंक शाखा में दोए एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिए हितग्राही को 10 लाख से एक करो ? रुपये तक का स्व.रोजगार ऋण दिया जाना है। प्रदेश में लगभग छह हजार बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। इस तरह प्रदेश के लिए 12 हजार का लक्ष्य है। स्टेण्ड.अप इंडिया तथा इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को मिलाकर प्रदेश में दस हजार युवाओं को उद्यमियों के रूप में पिछले वर्ष स्थापित किया गया है।

मेक इन इंडिया

भारत सरकार द्वारा मेन्युफेक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिये मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश प्रक्रिया को अधिक उदार बनानाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेसए बुनियादी और औद्योगिक अधोसंरचना के गतिशील निर्माण से संबंधित विभिन्न निर्णय लिये हैं।

मध्यप्रदेश में भी मेक इन इंडिया के संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इनमें प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार स्थापित करने और उनके संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया है। इसमें सशक्त सिंगल विण्डो प्रणाली से निवेशकोंध उद्यमियों को विविध सेवाएँ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटनए विद्युत कनेक्शनए प्रदूषण संबंधित अनुमतियाँए श्रम कानूनों के अधीन पंजीयनए औद्योगिक क्षेत्रों में बिल्डिंग प्लान का अनुमोदनए वॉटर कनेक्शनए वित्तीय रियायतें इत्यादि सेवाएँ उपलब्ध करायी गई हैं। श्रम कानूनों एवं प्रक्रियाओं में सुधार और ऑनलाइन सेवाएँए ई.स्टाम्प एवं दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयनए ऑनलाइन एलएण्टीएच एचएण्टीएच विद्युत

कनेक्शनए प्रदूषण अनुमतियों की ऑनलाइन उपलब्धताए नगर निगम क्षेत्रों में भवन निर्माण नक्शों का ऑनलाइन अनुमोदनए फायर अनापत्ति और कामर्शियल कोर्टस् की स्थापना इत्यादि पर भी कार्य किया गया है। उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिये उपयुक्त शासकीय भूमि का लैंड बैंक बनाया गया है।

निवेश प्रोत्साहन के लिये जीआईएस

राज्य में पूँजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट.2016 में विभिन्न सेक्टर्स के लिए रुपये 5७62 लाख करो ? के निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुए। उद्योगों से संबंधित रुपये 11 हजार 272 करो ? के पूँजी निवेश की 101 परियोजनाएँ स्थापित हो चुकी हैं। रुपये 37 हजार 537 करो ? के पूँजी निवेश की 99 परियोजनाएँ विभिन्न चरण में क्रियान्वयन अधीन हैं।

नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के कार्य

लगभग 2046 हेक्टेयर क्षेत्र में 19 नवीन आद्योगिक क्षेत्रों की 501 करो ? रुपये की परियोजना लागत से स्थापना का कार्य विभिन्न चरण में प्रक्रियाधीन है। साथ ही 13 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में 1941 हेक्टेयर भूमि पर 1180 करो ? रुपये के उन्नयन कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 09 नवीन आद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। यह औद्योगिक क्षेत्र 2९625 हेक्टेयर भूमि पर 1९914 करो ? रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किए जाएंगे।

नया एमएसएमई विभाग

प्रदेश के विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अप्रैल 2016 में सूक्ष्मए लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश उन छह राज्यों में से एक है जहाँ पृथक एमएसएमई विभाग है। राज्य शासन ने लघु उद्यमियों के लिए अनेक सुविधाएँ घोषित की हैं। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए पूँजी लागत सहायताएँ ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। एमएसएमई इकाइयों के लिए वैटए बिजली दरए मण्डी और एन्ट्री टैक्स आदि की छूट की सुविधा भी निर्धारित है। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति के चलते वर्ष 2016.17 में 87 हजार से ज्यादा



एमएसएमई इकाइयों का पंजीयन उद्योग आधार मेमोरण्डम में हुआ है जो इसके पूर्व वर्ष की संख्या का ढाई गुना है। इनमें प्रदेश में 9500 करो ? का पूँजी निवेश हुआ और 3 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस वर्ष सा ? सात लाख लोगों को एमएसएमई के माध्यम से स्व.रोजगार से जो ?ने का लक्ष्य रखा गया है।

एमएसएमई इकाइयों को और ब ?वा देने के लिये एक अक्टूबरए 2016 को एमएसएमई सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में भोपाल में स्थापित होने वाले टूल रूम का शिलान्यास भी हुआ।

युवा उद्यमी योजना

प्रदेश के 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 10 लाख से लेकर एक करो ? तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाने की योजना प्रारंभ की गई है। योजना के हितग्राहियों को 15 प्रतिशत पूँजी लागत सहायताएँ पाँच प्रतिशत ब्याज दर सहायता ;महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत ऋण तथा ऋण गारंटी ;सीजीटीएमएससी के माध्यम से ऋण दी जाती है। आवश्यक हैण्ड होल्डिंग मदद भी दी जाती है। योजना के प्रथम दो वर्षों में मध्यप्रदेश में 2९500 युवाओं को लाभान्वित कर औसतन रुपये 35 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। भारत सरकार की स्टेण्ड.अप इंडिया योजना में 10 लाख से लेकर एक करो ? तक का ऋण दिया जाता है। योजना में केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुदानध् सब्सिडी नहीं दी जाती है। मध्यप्रदेश उन बहुत कम राज्यों में से है जो

योजना को अपने बजट से संचालित कर रहा है।

मुख्यमंत्री स्व.रोजगार योजना

प्रदेश में मुख्यमंत्री स्व.रोजगार योजना लागू की गई है। योजना की पात्रता के लिये प्रदेश का मूल निवासीए न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना है। आवेदक एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकध् वित्तीय संस्थाध् सहकारी बैंक का डिफल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमिध् स्व.रोजगार योजना में सहायता प्राप्त कर चुका होए तो वह योजना का पात्र नहीं होगा। यह योजना उद्योगध् सेवाध् व्यवसाय क्षेत्र के लिए है। योजना में परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 20 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये एक लाख होगी। बीपीएलएलएल अनुसूचित जातिध् अनुसूचित जनजातिध् अन्य पिछ ?वर्ग ;क्रीमीलेयर को छो ?कर ऋणध् महिलाध् अल्पसंख्यकध् निःशक्तजन के लिये 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये दो लाख की मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है। ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत की दर अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगा। योजना में गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।



आलेख बेहतर पर्यटन सुविधाओं का साक्षी बना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित करने के लिये पर्यटन निगम के माध्यम से अनुकरणीय प्रयास किये गये हैं। पर्यटन नीति और पृथक से पर्यटन केबिनेट का गठन कर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। मध्यप्रदेश अब पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में बेहतर सुविधाओं का साक्षी बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश के पर्यटन स्थलों को पोषित करने के लिए बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सुरेन्द्र पटवा ने पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहूलियतों का विस्तार कराया है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि लगातार 3 वर्ष से बेस्ट टूरिज्म स्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने वाला प्रदेश बन गया है मध्यप्रदेश। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन में गरिमापूर्ण समारोह में यह अवार्ड प्रदान किए। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर प्रदेश को एक बार फिर एक साथ 10 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए।

नेशनल अवार्ड समारोह में मध्यप्रदेश में आयोजित श्रृंखला महोत्सव हनुवंतिया को मोस्ट टूरिस्ट प्रोडक्ट्स और मध्यप्रदेश टूरिज्म को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म श्रृंखला को बेस्ट हेरिटेज सिटी खरगोन को सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इण्डिया उज्जैन रेलवे स्टेशन को टूरिस्ट फ्रेण्डली रेलवे स्टेशन और इंग्लिश कॉफी टेबल बुक को एक्सिलेंस इन पब्लिसिंग का राष्ट्रीय अवार्ड मिला। प्रदेश को बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेण्डली स्टेट यूनियन टेराटोरी में फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ। सिंहस्थ.2016 में मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा प्रकाशित हिन्दी ब्रोशर को एक्सिलेंस इन पब्लिसिंग इन हिन्दी ब्रोशर का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। बेस्ट वाइल्ड लाइफगाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार पचमड़ी के श्री सईब खान को मिला।





मध्यप्रदेश पर्यटन को लगातार पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। पिछले वर्ष 5 और इसके पहले 6 राष्ट्रीय अवार्ड सहित अन्य अवार्ड प्राप्त हुए। अभी 25 अक्टूबर को प्रदेश के पर्यटन को एक और प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। पर्यटन पर्व के दौरान विभिन्न गतिविधियों के आयोजन और सर्वश्रेष्ठ सहभागिता के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन का चयन किया गया।

प्रदेश में पर्यटन को बड़ावा देने के

लिए पर्यटन केबिनेट का गठन किया गया है। प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड का भी गठन किया गया है। पर्यटन केबिनेट के अनुमोदन से पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बड़ावा देने के लिए पर्यटन नीति, 2016 जारी की गई। इसके पहले पर्यटन नीति, 2012 एवं 2014 आस्तित्व में थी पर नीति में संशोधन कर नयी नीति को पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में निजी भागीदार भी सुनिश्चित की जा रही है। पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के

लिए लगभग 500 हेक्टेयर का भूमि लैण्ड बैंक स्थापित किया गया है। निजी निवेशकों को हेरिटेज परि. सम्पत्तियों और मार्गसुविधा केन्द्रों के निर्वर्तन की सुविधा मुहैया कराने के लिये पूँजीगत अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 9 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है जिस पर तकरीबन 250 करोड़ रुपये की राशि के निवेश से पर्यटन की परियोजनाएँ स्थापित होंगी।

पर्यटन परियोजनाओं में पहले 13 गतिविधियाँ शामिल थीं अब 18 गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें हेल्थ फार्मस, ध्वेलेनेस सेंटर, म्यूजियम, एम्पोरियम, थीम पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फ़िल्म स्टूडियो, शूटिंग, अधोसंरचना, लाइट एण्ड साउण्ड, शोलेजर, शो कैरेवान एवं करूज टूरिज्म आदि नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पूर्व में प्रचलित पर्यटन नीति में चयनित स्थलों पर अनुदान के स्थान पर अब पूरे प्रदेश में स्थापित परियोजनाओं को अनुदान की पात्रता में शामिल किया गया है। जल, पर्यटन को बड़ावा देने के उद्देश्य से 15 वॉटर बॉडी अधिसूचित की गई हैं। इसमें लैण्ड अलोकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सर्किट के लिए 92 करोड़ 21 लाख रुपये, हेरिटेज सर्किट के लिए 99 करोड़ 77 लाख रुपये, बुद्धिस्ट सर्किट





के लिए 74 करोड़ 94 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

मध्यप्रदेश में प्रकृति की सुन्दरता वन क्षेत्र हरियाली नेशनल पार्क वन्य जीवन

और पर्यटन स्थलों ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से दो प्रमुख महाकालेश्वर उज्जैन और ओंकारेश्वर मध्यप्रदेश में स्थित हैं। विश्व धरोहर श्रृंखला की तीन धरोहर, भीम बैटकाए साँची और खजुराहो के साथ सतपुड़ा की रानी पचमड़ी मांडू

महेश्वरए ओरछा भेड़ाघाट जबलपुरए चंदेरी ग्वालियर जैसे अनेक पर्यटन स्थल पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। हनुवंतिया में जलमहोत्सव का तीसरी बार आयोजन प्रमुख उपलब्धियों में शुमार हो गया है। गांधी सागर डेम पर विभिन्न पर्यटन सुविधाएँ विकसित करने का काम अंतिम दौर में है। मध्यप्रदेश में पर्यटन के जितने रंग बिखरे हैं उतने किसी अन्य प्रदेश में शायद ही हों। यहाँ ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर और धार्मिक पर्यटन के ऐसे अनेक स्थान हैं जिनका पर्यटक लुप्त उठाते हैं। पर्यटन स्थल सैलानियों को आल्हादित करते हैं।

पर्यटन विकास निगम के स्थापना

दिवस पर निगम ने अपनी विकास यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए पर्यटन विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत

टीम पुरस्कार की पात्रता की श्रेणी में शामिल की गई। पर्यटन निगम के 72 आवासीय एवं 6 गैर.आवासीय होटल संचालित हैं। निगम की होटलों को और अधिक

सुविधाजनक बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में प्रदेश में आने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2016.17 में 15 करोड़ 5 लाख से अधिक पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर आए। इनमें 3 लाख 63 हजार विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

पर्यटन विकास अब मध्यप्रदेश का ब्राण्ड बन गया है। पर्यटन निगम के ऑडियो.वीडियो की देश.विदेश में चर्चा होने लगी है। अब वह दिन दूर नहीं जब पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश विश्व के नक्शे पर साफसाफदिखने लगेगा।



किया है। चौकीदारए भृत्य रसोइया को भी पुरस्कारों से नवाजा गया है क्योंकि पूरी



मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास का एक दशक

मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जहाँ पृथक से पर्यटन केबिनेट का गठन हुआ। राज्य ने अपनी पर्यटन नीति-2016 बनाकर लागू कर दी है। नीति पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों के अनुकूल, सरल एवं उदार बनायी गयी है। इसमें अनुदान एवं अन्य नियमों का सरलीकरण किया गया है। अब पूरे प्रदेश में कहीं भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर निवेशकों को 15 से 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी सीमा 10 करोड़ तक होगी। नीति में शासकीय भूमि पर स्थापित होने वाली पर्यटक परियोजनाओं को स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से भी मुक्त रखा गया है।

रोजाना के जीवन में पर्यटन के बढ़ते महत्व और पर्यटन विकास को देखते हुए मध्यप्रदेश में वर्ष 1978 में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। आज यह संस्था न केवल अपने गठन के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है बल्कि उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर भी है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में जो मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लगभग बंद होने की कगार पर था उसी निगम के बजट में पिछले 10 वर्ष में 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की संख्या में भी 10 से 15 फीसदी इजाफा हुआ है। वस्तुतः यह एक बंद होने के कगार पर खड़ी संस्था को पुनर्स्थापित करने या ऋद्धि करने की सफल कहानी है जो अन्य संस्थानों के लिये अनुकरणीय होने के साथ षडुह्यद्द स्लूहस्र4 का भी उपयुक्त विषय है।

प्रथम जल-महोत्सव का हनुवंतिया में सफल आयोजन किया गया। हनुवंतिया में वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर ऋजू, मोटर बोट एवं जलपरी का संचालन किया जा रहा है। द्वितीय जल महोत्सव 15 दिसम्बर 2016 से 15 जनवरी 2017 तक आयोजित किया जायेगा। हनुवंतिया में हाउस बोट के संचालन की तैयारी है।

हनुवंतिया की तर्ज पर ओंकारेश्वर के नजदीक सैलानी टापू पर नया वॉटर स्पोर्ट्स केन्द्र विकसित किया जा रहा है। यह स्थान ओंकारेश्वर बाँध परियोजना के नजदीक स्थित है।

यहाँ रिसॉर्ट और बोट क्लब का निर्माण अंतिम चरण में है।

प्रथम राज्य स्तरीय अवार्ड्स स्थापित कर कुल 30 श्रेणी में 39 अवार्ड्स वितरित किये गये। पहली बार जिला स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों के लिये पर्यटन क्रिज का आयोजन किया गया। कुल 3675 स्कूलों के लगभग 11 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भागीदारी की। राज्य स्तर पर पर्यटन क्रिज के फाइनल राउण्ड का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण किया जा चुका है।

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स

पर्यटन विभाग भारत शासन से स्वीकृत केन्द्रीय योजना पर्यटक परिसर नीमच का शिलान्यास एवं बाँधवगढ़ में पर्यटक स्वागत केन्द्र का लोकार्पण इस अवधि में किया गया। चंदेरी में निर्मित इकाई ताना-बाना का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ किया गया। साथ ही राजगढ़ जिले के ब्यावरा तथा सीहोर जिले के डोडी में संचालित इकाई के विस्तार एवं उन्नयन कार्य की शुरुआत की गई।

भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में वाइल्ड लाइफ सर्किट के लिये 92 करोड़ 21 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है। बुद्धिस्ट सर्किट परियोजना के लिये भारत सरकार द्वारा 75 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हेरिटेज सर्किट विकास के लिये 98 लाख रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है।

हेरिटेज पर्यटन विकास के लिये निवेशकों को नये अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं। रूपये एक लाख की अपसेट

आलेख

किसान की आय बढ़ाने रोडमैप तैयार कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सर्वोपरि



किसानों की अथक मेहनत से आज प्रदेश कृषि विकास के क्षेत्र में सर्वोपरि है। प्रदेश को निरंतर पाँच कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। पिछले पाँच वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर औसतन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। प्रदेश आज दलहन, तिलहन उत्पादन चना मसूर सोयाबीन अमरूद टमाटर लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम है। गेहूँ अरहर सरसों आँवला संतरा मटर धनिया उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। सम्पूर्ण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है।

पाँच वर्ष में किसान की आय को दोगुना करने का रोडमैप तैयार

मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले किसानों की आय पाँच

वर्षों में दोगुनी करने का रोडमैप बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रोडमैप के अंतर्गत मुख्यतः पाँच आधार बिन्दु क्रमशः कृषि लागत में कमी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कृषि विविधीकरण उत्पाद का बेहतर मूल्य और कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर कार्य किया जा रहा है। कृषि उद्यानिकी पशुपालन मछलीपालन वानिकी सिंचाई विस्तार रेशम कुटीर एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों द्वारा रोडमैप पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिला स्तर का रोडमैप तैयार कर लिया गया है एवं ग्राम स्तर का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुनी करने के लिये कटिबद्ध है।

वर्ष 2004.05 में प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन मात्र 2 करोड़ 14 लाख मीटन था जो वर्ष 2016.17 में बढ़कर 5



करोड़ 44 लाख मीण्टन हो गया है। प्रमाणित जैविक कृषि के क्षेत्र में प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर करने की दिशा में राज्य सरकार अग्रसर है।

प्रदेश देश में बीज प्रमाणीकरण में अग्रणी है। देश में प्रत्येक सात प्रमाणित बीज में से एक प्रदेश में होता है। अब तक प्रदेश में निजी क्षेत्र में लगभग 1800 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इससे किसानों को सस्ती दर पर आधुनिकतम कृषि यंत्र किराए पर सुलभ हो रहे हैं।

खरीफ 2015 का राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का 201 लाख से अधिक कृषकों को आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 4661 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 50 लाख किसानों को जोड़ा जा चुका है। खरीफ 2016 की 1880 करोड़ की बीमा दावा राशि का कृषकों के खातों में समायोजन एक माह में होने जा रहा है। प्रदेश की स्वयं की किसान हितैषी बीमा योजना बनाने की कार्यवाही प्रचलित है।

सभी विकासखण्डों में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण तथा सभी संभाग में अर्थात् दस उर्वरक और बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य जारी है। अब तक प्रदेश के 85 लाख 50 हजार किसानों को निःशुल्क स्वाइन हेल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं। कार्ड की सिफरिशों के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग करने से पैदावार में बढ़ोत्तरी एवं लागत में कमी होगी। कृषि उत्पादक संगठनों फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से जुड़े लगभग तीन लाख किसानों को भण्डारण विपणन मूल्य संवर्द्धन खाद्य प्र.संस्करणों से जोड़ा जा रहा है

1000 करोड़ के मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन



मध्यप्रदेश में किसानों को बाजार हस्तक्षेप दर के अनुसार उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 1000 करोड़ रुपये का मध्यप्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया है। राज्य शासन ने कोष के लिये कार्यकारिणी समिति का गठन किया है। कोष का गठन जिन उद्देश्यों के लिये किया गया है उनमें जिन जिंसों का केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है उन जिंसों के मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित बाजार हस्तक्षेप दर ;मार्केट इंटरवेंशन रेट पर किये गये उपार्जन में हानि की स्थिति में उपार्जन संस्था को इस कोष से राशि दी जायेगी। केन्द्र सरकार के प्राइस स्टेबलाइजेशन फण्ड से वित्त हानि के लिये प्राप्त राशि को इस कोष में जमा किया जायेगा। इस कार्य में लाभांश प्राप्त होने पर भी कोष में लाभांश की राशि जमा की जायेगी। कोष में उपलब्ध राशि पर ब्याज की राशि प्राप्त होने पर उसे भी कोष में जमा करवाया जायेगा। कोष का संधारण राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। कोष में 500 करोड़ रुपये मण्डी बोर्ड की राज्य विपणन विकास निधि से तथा शेष राशि राज्य शासन के बजट प्रावधान किये जाने के बाद कोष में जमा करवायी जायेगी। कृषि केबिनेट इस कोष की साधारण सभा होगी और उसके द्वारा कोष की नीति का निर्धारण किया जायेगा। कोष की कार्यकारिणी समिति द्वारा साधारण सभा ;कृषि केबिनेट के निर्णय के अनुसार कोष के संचालन का कार्य किया जायेगा।

मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग गठित

प्रदेश में कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन की बेहतर

सुविधाओं संबंधी अनुशंसा करने के लिये श्मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग खरीफ रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों की लागत की गणना कर राज्य शासन को अनुशंसा करेगा। राज्य सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना में अपेक्षा किये जाने पर चयनित जिन्स की बाजार हस्तक्षेप दर के लिये राश्या शासन को सुझाव भी देगा। कृषि विपणन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये सुझाव देने के साथ शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर विभिन्न फसलों के लिये अध्ययन करेगा। आयोग शासन को आवश्यकतानुसार कृषि मूल्य संबंधी एवं अन्य उत्पादन संबंधी समस्याओं पर सलाह भी देगा। इसके अलावा आयोग राज्य शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगा। आयोग खरीफ रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की अवधि से पहले प्रतिवर्ष राज्य शासन को तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना

राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2017 से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की जा रही है। योजना में दलहनी तिलहनी एवं उद्यानिकी फसलों का किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए श्ममर्थन मूल्य या बाजार हस्तक्षेप दरश् तथा किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपजए मंडी समिति के प्रांगण में बेचे जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर घोषित मॉडल विक्रय दर की अंतर राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाना तय किया गया है।

कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना

ग्रामीण युवाओं के लिए कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स की योजना जल्दी ही प्रारंभ की जा रही है। इसमें युवा को 25 लाख तक के कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। केन्द्रों पर किसान अपने कृषि-उद्यानिकी उत्पाद लाकर उनकी क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकिंग मूल्य सर्वेद्धन किराए पर करा सकेंगे। दो वर्षों में ऐसे एक हजार कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों को प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है।

सिंचाई सुविधा का विस्तार

प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा विगत पाँच वर्ष में सिंचाई क्षमता 23 लाख 23 हजार से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर की गई है। पिछले वर्ष स्वीकृत 159 सिंचाई परियोजनाओं से करीब सवा दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। जिन क्षेत्रों में पारम्परिक माध्यमों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं था वहाँ भी पर ड्राप मोर क्राप कार्यक्रम से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

इस वर्ष सिंध द्वितीय चरणए भानपुरा नहर एवं बरियारपुरए 8 मध्यम एवं 105 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर

सिंचाई क्षमता में पौने दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बड़ोत्तरी का लक्ष्य है।

नर्मदा घाटी की सिंचाई योजनाएँ

नर्मदा घाटी में 14 माइक्रो उद्ग्रहन सिंचाई योजनाओं का कार्य चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे नहर सिंचाई से वंचित 3 लाख 59 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित हो सकेगा। अब नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक के बाद दूसरे चरण में नर्मदा-मालवा-गम्भीर लिंक का कार्य पूरा होने को है। इससे उज्जैन-इन्दौर जिलों में पचास हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र निर्मित होगा। नर्मदा-कालीसिंध और नर्मदा-पार्वती लिंक का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा। बड़ी नर्मदा सिंचाई योजनाओं से गत वर्ष सिंचित साड़े 5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को बढ़ाकर इस वर्ष 6 लाख हेक्टेयर किया जायेगा।

कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो गया है। प्रदेश की उपलब्ध क्षमता बढ़कर 17 हजार 766 मेगावॉट हो गयी है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली दी जा रही है। गत रबी मौसम में 11 हजार 423 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति की गयी जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। इस वर्ष रबी में 12 हजार मेगावॉट से अधिक मांग की आपूर्ति की तैयारी की गयी है।

अजा . अजजा कृषकों को 5 एचपी पंप पर मुफ्त बिजली

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 हार्सपावर तक के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। अन्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी प्लेट रेट पर मात्र 1400 रुपये प्रति हार्सपावर वार्षिक दर से बिजली दी जा रही है। गत वर्ष कृषकों को और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबी रेखा के घरेलू उपभोक्ताओं को 25 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने के एवज में 8271 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गई। इस वर्ष 8736 करोड़ की सबसिडी का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में अस्थायी कनेक्शनों को स्थायी में बदलने के साथ नये स्थायी कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं। इस पहल का ही परिणाम है कि स्थायी कृषि पंप कनेक्शन ब ?कर लगभग 24 लाख हो गये हैं।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना

श्मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना प्रारंभ की गई है। योजना में केन्द्र और राज्य शासन द्वारा 85 से 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जायेगा। किसानों को सिर्फ दस से पन्द्रह प्रतिशत राशि देनी होगी। सोलर पम्प से किसानों को फायदा होने के



साथ सरकार पर बिजली बिल के अनुदान के वित्तीय भार में कमी आयेगी।

25 हजार करोड़ के फसल गण वितरण का लक्ष्य

प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल गण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2003.04 में कृषकों को 1274 करोड़ का फसल गण वितरित किया गया था जो वर्ष 2016.17 में रुपये 11 हजार 941 करोड़ हो गया है। इस वर्ष कृषकों को 25 हजार करोड़ के फसल गण के वितरण का लक्ष्य है। राज्य शासन द्वारा 2334 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान सहकारी बैंकों को दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी गण सहायता योजना में 177 करोड़ रुपये का अनुदान इस वर्ष प्राथमिक सहकारी साख समितियों को उपलब्ध कराया गया है। योजना से लगभग 16 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश में दिसम्बर 2016 तक 77 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इनमें सहकारी बैंकों की भागीदारी 69 प्रतिशत रही है। सहकारी बैंकों से प्रतिवर्ष 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य है।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ मक्काए धान का उपार्जन

समर्थन मूल्य पर गेहूँ धान एवं मक्का आदि खाद्यान्न का उपार्जन किया जा रहा है। खरीफ 2016.17 में 918 खरीदी केन्द्रों में 2 लाख 88 हजार किसानों से रुपये 2883 करोड़ से ज्यादा मूल्य का धान उपार्जित किया गया। इसी तरह 248 खरीदी केन्द्रों में 28 हजार किसानों से रुपये 321 करोड़ से ज्यादा मूल्य की मक्का उपार्जित की गई है। रबी वर्ष 2017.18 में 2989 खरीदी

केन्द्रों से 7 लाख 39 हजार कृषकों का रुपये 10 हजार 928 करोड़ से ज्यादा मूल्य का गेहूँ उपार्जित किया गया है।

कृषकों को बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास

अपेक्स एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं में कोर. बैंकिंग सेवाएँ प्रारंभ करने के साथ एनईएफ्टी एसएमएस एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। एटीएम सुविधा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राथमिकी कृषि सहकारी साख समितियों के सदस्य कृषकों को बैंकिंग से जोड़ने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं में 18 लाख के डिजिटल मेम्बर रजिस्टर तैयार कराये गये हैं। इन खातों पर रूपे केसीसी कार्ड जारी किये जाकर कृषक नगद गण एटीएम से तथा वस्तु गण पैक्स स्तर पर माइक्रो एटीएम से प्राप्त कर सकेंगे।

बाजार हस्तक्षेप से 8 रुपये प्रति किलो प्याज की खरीदी

प्रदेश में पिछले वर्ष प्याज का अत्यधिक उत्पादन होने तथा प्याज की घटती कीमत को देखते हुए शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप का निर्णय लेते हुए 4 हजार 482 किसानों से 62 करोड़ 42 लाख कीमत की 10 लाख 40 हजार से ज्यादा क्विंटल प्याज खरीदी गई। इस वर्ष भी रुपये 800 प्रति क्विंटल की दर से किसानों से 701 करोड़ रुपये कीमत की 8 लाख 76 हजार से ज्यादा क्विंटल प्याज की खरीदी गई।

समर्थन मूल्य पर 10 जून से खरीदी प्रारंभ कर अभी तक लगभग रुपये 1700 करोड़ की साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन

दलहन फसलें भी ऋय की गई हैं। इस हस्तक्षेप से प्रचलित मण्डी दरों के मुकाबले लगभग 1002 करोड़ की अतिरिक्ति आय किसानों को संभव हो सकी। मध्यप्रदेश कृषि उपल मंडी अधिनियम 2012 में संशोधन कर केला को छोड़कर सभी फलों को मंडी प्रांगण से बाहर फल.सब्जी के विक्रय को विनियमन से मुक्त किया गया है। इससे किसानों को सीधे फल.सब्जी खुले बाजार में बेचने का विकल्प मिला है।

खरीफ 2017 में 6 लाख 85 हजार मीण् टन का रिकार्ड अग्रिम भण्डारण कर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। किसानों द्वारा उठायी गयी रासायनिक खादों पर ब्याज की छूट भी दी गई।

उद्यानिकी फसलों का क्लस्टर में विस्तार

प्रदेश में उद्यानिकी के विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्यानिकी फसल क्षेत्रफल बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। आज प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 262 लाख मी. टन तक पहुँच गया है। उद्यानिकी फसलों का क्लस्टर में विस्तार कराया जा रहा है। उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि को बनाये रखने के लिये उत्पादकों को गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री प्राप्त होने पर विशेष ध्यान दिया जाकर आगामी पाँच वर्षों में 100 उद्यानिकी नर्सरियों का उन्नयन किया जायेगा। इन रोपणियों के उन्नयन से कृषकों को उन्नत पौध सामग्री उचित दर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। फसलोत्तर प्रबंधन के दिशा में विशेष प्रयास किये जाकर नश्वर उत्पादों के भण्डारण के लिये दो वर्षों में 5 लाख मी.टन शीत भण्डारण एवं 5 लाख मी.टन प्याज भण्डारण क्षमता में वृद्धि की जा रही है। उद्यानिकी में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कम समय में कृषि कार्य पूर्ण हो सकेगा एवं उत्पादन लागत को नियंत्रित

किया जा सकेगा।

कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के प्र.संस्करण के लिये नयी नीति बनाकर लघु एवं मध्यम प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे खाद्य प्र.संस्करण उद्योग से नवीन रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। पिछले वर्ष में करीब 13 हजार कृषकों और इस वर्ष 18 हजार कृषकों को उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन 13.45 मिलियन टन हुआ

प्रदेश का दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष 10.69 प्रतिशत वृद्धि के साथ बढ़कर 13.45 मिलियन टन हो गया है। गोकुल महोत्सव के जरिये 97 हजार से ज्यादा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर करीब 33 लाख पशुपालकों और दो करोड़ पशुओं का पंजीकरण 33 लाख पशुओं का उपचार एक लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण तथा 5 लाख पशुओं के बांझपन का उपचार किया गया। पहली बार एफएमडी कन्ट्रोल प्रोग्राम क्रियान्वित कर प्रदेश के दो करोड़ से ज्यादा गौ.वंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया। करीब 66 लाख भेड़.बकरियों का पीपीआर और रीवा संभाग के चार जिलों में ढाई लाख पशुओं का बसेला टीकाकरण किया गया।

प्रदेश में पहली बार उपभोक्ताओं को उनकी माँग के आधार पर घर पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिये मोबाईल एप बनाया गया है। नवीन मिल्क रूट का गठन एवं युक्तियुक्तकरण के उद्देश्य से 730 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया और 2344 ग्रामों में दुग्ध संकलन केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिये 620 रुपये प्रति किलो फेट निर्धारित किया गया। यह अभी तक की सर्वाधिक दुग्ध ऋय दर है।

उपलब्ध जलक्षेत्र के 98

प्रतिशत में मछली पालन

प्रदेश के सिंचाई जलाशयों एवं ग्रामीण तालाबों के कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 98 प्रतिशत मछली पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है। पिछले वित्त वर्ष में एक लाख चौरासी हजार नौ सौ तैंतीस मछुआरों का दुर्घटना बीमा कराया गया जो अभी तक का सर्वाधिक दुर्घटना बीमा है। इस वर्ष एक लाख छयासी हजार चार सौ सत्रह मछुआरों को बीमा योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों की तरह मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर गण सुविधा उपलब्ध कराने फिशरमेन क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे हैं। अभी तक कुल 58 हजार 550 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं। बड़े शहरों में 8 थोक एवं छोटे कस्बों में 170 पुटकर मत्स्य बाजारों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में पंगेशियस एवं गिफ्ट तिलापिया जैसी आधुनिक पद्धति से मत्स्य.पालन शुरू किया गया है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण

प्रदेश भर में किसानों के सीमांकन एवं अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बँटवारा प्रकरणों के निराकरण और गण पुस्तिका प्रदाय करने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी कृषि भूमि के इस संबंध में होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। स्मामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में आय के साधन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

खेती से जनसंख्या का बोझ कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। किसान परिवारों के युवा खेती के अलावा कृषि आधारित उद्योग लगायें इसके लिये मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना बनाई जा रही है। जिसमें उन्हें दस लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का गण उपलब्ध कराया जायेगा।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम



मध्यप्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। उच्च शिक्षा ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्म-निर्भर भी बनाती है। मध्यप्रदेश युवाओं की सृजनशील क्षमताओं के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये लगातार सफल प्रयास कर रहा है। इसी का परिणाम है कि उच्च शिक्षा का सकल पंजीयन अनुपात (जी.ई.आर.) वर्ष 2014-15 में बढ़कर 20.04 हो गया है। वर्ष 2013-14 में यह 19.07 प्रतिशत था। वाणिज्य विषय में विद्यार्थियों की रुचि अधिक होने की वजह से प्रत्येक संभाग में एक-एक महाविद्यालय को वाणिज्य विषय के लिये उत्कृष्ट संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिये 2666 करोड़ की विश्व बैंक परियोजना स्वीकृत हो चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 54 महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। व्याख्यान यू-ट्यूब पर भी डाले जा रहे हैं। वाई-फाई की सुविधा 122 महाविद्यालय में उपलब्ध करवायी गयी है। साथ ही 15 महाविद्यालय में ई-रिसोर्स सेंटर स्थापित किये गये।

विद्यार्थियों को घर के पास ही उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विगत 3 वर्ष में 18 नवीन शासकीय महाविद्यालय, 3

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय और 63 नये संकाय स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही 45 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गयी। तीन नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये।

व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ

विद्यार्थियों में पाठ्यक्रमों के अध्ययन के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति और परम्परा की जानकारी देने के उद्देश्य से व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके माध्यम से पहला व्याख्यान दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी पर हुआ। इसके बाद हर माह महाविद्यालयों में विभिन्न विषय पर व्याख्यान करवाये जा रहे हैं। इससे लगभग एक लाख 20 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सभी शासकीय महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ स्थापित हो चुके हैं। सभी जिलों में युवा केन्द्र की स्थापना की गयी है।

महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धता और माँग के अनुसार विषयों का युक्ति-युक्तकरण किया गया। भोपाल में ही लगभग 750 पद का युक्ति-युक्तकरण किया गया। यह प्रक्रिया सभी जिलों में की जायेगी। महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिये 1646 रिक्त पद की भर्ती के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखा गया। विभिन्न विभाग में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ 175 प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की



प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें महाविद्यालयों में पदस्थ किया गया है। साथ ही दूरस्थ अंचल के महाविद्यालयों में बड़े शहरों से सहायक प्राध्यापक स्थानांतरित किये गये, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन में सुविधा हो। नजदीकी महाविद्यालयों से प्राध्यापकों की कमी वाले महाविद्यालयों में प्राध्यापकों का डिप्लायमेंट भी किया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय में दो विभाग को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ की समय पर उपस्थिति करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगवाई जा रही हैं।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राध्यापक-सहायक प्राध्यापक तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार योजना में पुरस्कारों की संख्या 30 से बढ़ाकर 248 कर दी गयी है। इसमें 8 प्राचार्य, 40 शिक्षक एवं 200 विद्यार्थी को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। कौशल विकास कार्यक्रमों में 29 हजार 516 विद्यार्थी को प्रशिक्षित किया गया।

विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक परिदृश्य से जोड़ने के लिये प्रत्येक संभाग में एक-एक महाविद्यालय का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी के लिये चयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल को इस कार्य के लिये मॉडल संस्थान बनाया गया है।

अशासकीय महाविद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभागायुक्त/कलेक्टर एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाये गये। निरीक्षण में कमियाँ पायी जाने पर 110 महाविद्यालय की मान्यता समाप्त की गयी। इन महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं हुए।

उच्च शिक्षा के सतत विकास एवं विशेषकर छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिये गाँव की बेटा योजना तथा शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार की बेटा के लिये प्रतिभा किरण योजना लागू की गयी है। दोनों योजनाओं के लाभान्वितों की संख्या में निरंतर उत्साहजनक वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014-15 में गाँव की बेटा योजना में लगभग 2500 लाख का व्यय हुआ, जिसमें 3800 से अधिक छात्राएँ लाभान्वित हुईं। प्रतिभा किरण में 200 लाख का व्यय हुआ, जिसमें लगभग 3200 छात्राएँ लाभान्वित हुईं।

महाविद्यालयों का NAAC द्वारा मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना में NAAC मूल्यांकित ए-ग्रेड महाविद्यालय को 15



लाख, बी-ग्रेड महाविद्यालय को 10 लाख एवं सी-ग्रेड महाविद्यालय को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी। इस वर्ष 28 महाविद्यालय नेक द्वारा मूल्यांकित हुए हैं। इनमें 10 महाविद्यालय को ए-ग्रेड, 15 महाविद्यालय को बी-ग्रेड एवं 3 महाविद्यालय को सी-ग्रेड प्राप्त हुई है।

रूसा में विश्वविद्यालय-महाविद्यालय के विकास के लिये 269 करोड़ स्वीकृत

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में प्रदेश के एक ऑटोनोमस कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने, 3 विश्वविद्यालय में अधोसंरचना विकास, 5 नये मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने, 2 डिग्री कॉलेज को मॉडल कॉलेज में अपग्रेड करने और 30 महाविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट स्वीकृत की गयी है। इन कार्यों के लिये कुल 269 करोड़ रुपये 12वें प्लान में स्वीकृत किये गये हैं। इसमें से इस वित्तीय वर्ष में 134 करोड़ 50 लाख रुपये मिलेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने स्वीकृत कार्य प्रोजेक्ट के अनुसार शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

रूसा में पं. एस.एन. शुक्ला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। इसके लिये 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को अधोसंरचना विकास के लिये 20-20 करोड़ दिये जायेंगे। झाबुआ, श्योपुर, हरदा, डिण्डोरी और उमरिया में नये मॉडल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक के लिये 12-12 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। शासकीय महाविद्यालय सिहोरा जिला जबलपुर और मासिक पत्रिका

शासकीय महाविद्यालय देपालपुर जिला इंदौर को मॉडल डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करने के लिये 4-4 करोड़ मिलेंगे। इसके लिये रूसा में 26 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अगस्त को झाबुआ में मॉडल कॉलेज का भूमि-पूजन किया।

गीतांजलि और हमीदिया कॉलेज को मिलेंगे 2-2 करोड़



रूसा में 30 महाविद्यालय को अधोसंरचना विकास के लिये 2-2 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। भोपाल के शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय और हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय को 2-2 करोड़ मिलेंगे। इसी तरह शासकीय एम.के.बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर, महात्मा गाँधी स्मृति महाविद्यालय होशंगाबाद, कन्या महाविद्यालय खण्डवा, कन्या पी.जी. महाविद्यालय सागर, पी.जी. महाविद्यालय मंदसौर, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय सीहोर, स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय नरसिंहपुर, कन्या महाविद्यालय सीहोर,

कन्या महाविद्यालय विदिशा, पी.जी. महाविद्यालय दतिया, कन्या महाविद्यालय एवं जयवंती हक्सर महाविद्यालय बैतूल, पी.जी. महाविद्यालय बड़वानी, श्री नीलकण्ठेश्वर महाविद्यालय खण्डवा, चन्द्रविजय महाविद्यालय डिण्डोरी, कन्या महाविद्यालय कटनी, रानी दुर्गावती महाविद्यालय मण्डला, पी.जी. महाविद्यालय सतना, महाराजा महाविद्यालय छतरपुर, पी.जी. महाविद्यालय सागर, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय एवं एम.एल.बी. महाविद्यालय ग्वालियर, पी.जी. महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय टीकमगढ़, माता जीजा बाई कन्या महाविद्यालय इंदौर और शासकीय होम साइंस कन्या महाविद्यालय होशंगाबाद को भी 2-2 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

विषय निरंतरता के आवेदन भी ऑनलाइन

योजनाओं की सतत मॉनीटरिंग के लिये स्काइप के माध्यम से अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। सत्र 2015-16 में पहली बार प्रायवेट महाविद्यालयों में विषय एवं पाठ्यक्रम की निरंतरता संबंधी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये गये।

एन.सी.टी.ई. से संबंधित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिये भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया गया। बी.पी.एड., एम.पी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई। इस तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न नवाचार एवं अधोसंरचनात्मक सुधारों से उच्च शिक्षा को ओर विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

आलेख

क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरी ड्रीम सिटी की दिशा में बढ़ता मध्यप्रदेश

जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का है। स्वच्छता के बिना हम निरोग नहीं रह सकते हैं। भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्थाएँ गाँव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की उपलब्धता अभियान के उद्देश्यों में शामिल है।

क्या है ओ डी एफ

खुले में शौच की समस्या समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती है। जहाँ एक तरफ यह जन स्वास्थ्य वृ विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए बड़ा खतरा है वहीं दूसरी तरफ यह वृद्धों और निशक्तजनों के लिए असुविधा का कारण है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव



महिलाओं के स्वास्थ्य निजता गरिमा और सुरक्षा पर पड़ता है। स्वास्थ्य कुपोषण जैसी समस्याओं के बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक है कि वातावरण को खुले में शौच से पूर्णता मुक्त बनाया जाये तथा प्रत्येक स्तर पर इसकी संवहनीयता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाये। खुले में शौच से मुक्त का मतलब खुले में कहीं

भी मानव मल का दिखाई न देना सभी प्रकार के निजी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाले मल का सुरक्षित निपटान हो जिससे कि वातावरण दूषित न हो। साथ ही निजी साफसफाई के लिए अपेक्षित व्यवहारों पर बल देना शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान





प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटक के मध्य प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति कृत.संकल्पित है। श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मिशन के तहत प्रदेश को खुले से शौच मुक्त तथा

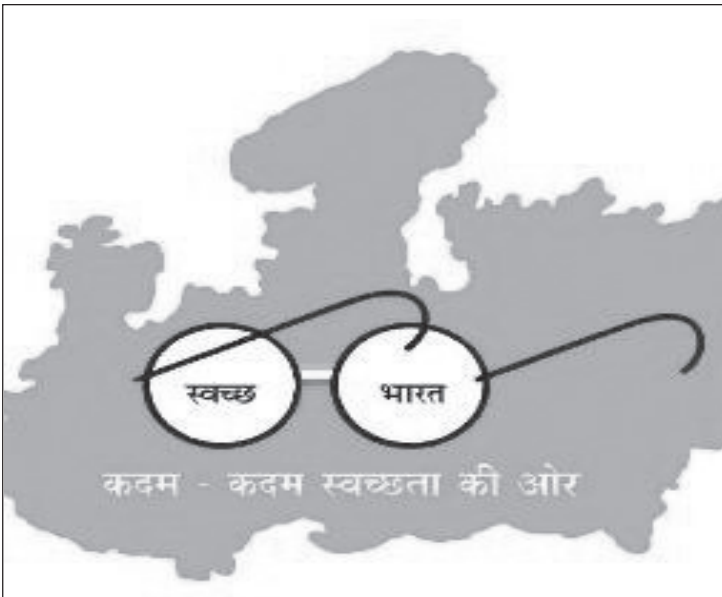
शहरी कचरे के प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयासरत है। खुले में शौच को जन स्वास्थ्य के लिए व्यापक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में खुले में शौच मुक्त अभियान ने एक जनांदोलन का रूप ले लिया है। लोग साफ.सफाई का महत्व जानकर न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक स्वच्छता के लिए जागरूक हुए बल्कि अपने परिवेश शहर प्रदेश और देश की स्वच्छता के लिए प्रदेश की

जनता ने भी यह ठान लिया है कि अब हमें खुले में शौच से मुक्ति चाहिए। लोगों ने श्रम समय और अर्थ दान कर मिशन में योगदान किया।

खुले में शौचमुक्त प्रदेश की ओर बढ़ते कदम

अनेक शहरों में स्थानीय महिलाओं पुरुषों और बच्चों की टोलियों ने खुले में शौच के लिए जा रहे लोगों को समझाइश देकर उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। निगरानी दलों ने सबेरे.सबेरे

प्रोको.टोको अभियान चला कर ए लोटा गैंग बनाकर सीटियाँ बजाकर खुले में शौच जा रहे लोगों को रोका और उन्हें शौचालय का रास्ता दिखलाया। ये छोटे परन्तु महत्वपूर्ण योगदान हैं जो एक.एक ईंट कर



स्वच्छ.स्वस्थ मध्य प्रदेश की बुनियाद रख रहे हैं। प्रदेश सरकार भी अपने सुधीजनों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर चलने को तत्पर है। पिछले तीन साल में लगभग 4 लाख 70 हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया है। चलित आबादी के लिए भी राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिकधसामुदायिक शौचालयों में करीब बारह हजार सीटों का निर्माण करवाकर इनका संचालन और साफ.सफाई सुनिश्चित की गई हैं।

इसी का परिणाम है कि शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश के सभी 378 निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार की अधिकृत संस्था द्वारा इनमें से 285 शहरों को खुले में शौच मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। जल्द ही यह संस्था अन्य निकायों में भ्रमण कर उन्हें भी यह प्रमाण.पत्र दे देगी। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही मध्यप्रदेश अधिकारिक रूप से खुले में शौच मुक्त प्रदेश बन जाएगा। स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से आर्थिक विकास सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रदेश एक लम्बा रास्ता तय कर यहाँ तक पहुँचा है। प्रदेश में जिस प्रकार से अभी तक आम लोग इस आन्दोलन की बागडोर संभाल रहे थे वैसे ही आगे भी प्रदेश के नागरिकों की ही यह जिम्मेदारी होगी कि निर्मित शौचालयों का समुचित उपयोग और रख.रखाव कर खुले में शौच की प्रथा को प्रदेश से हमेशा के लिए समाप्त करे।

ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन

प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में पहले से ही सजग हो कर कार्य कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय को 26 क्लस्टर में बाँट कर जन.निजी भागीदारी व्यवस्था से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 6 क्लस्टर आधारित परियोजनाएँ कचरे से बिजली बनाने तथा 20 परियोजनाएँ कचरे से खाद बनाने की हैं। जबलपुर क्लस्टर में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। रुपये 1555 करोड़ की लागत की कचरे से बिजली बनाने की सभी 6 परियोजना के कार्यशील होने के बाद प्रदेश के 78 निकाय में प्रतिदिन पैदा हो रहे लगभग 3500 टन कचरे से 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा।

रूपये 1326 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 20 कचरे से खाद बनाने वाली परियोजनाओं से प्रदेश के 300 निकायों में रोड के लगभग 3000 टन कूड़े को घर-घर से संग्रहीत और उपचारित कर लगभग 450 टन जैविक खाद भी बनायी जायेगी। कचरे के उचित प्रबंधन द्वारा जैविक खाद बनने और इसके कृषि कार्यों में उपयोग से प्रदेश के किसान की आमदनी में वृद्धि होने के साथ ही भूमि भी अधिक उर्वरा होगी और खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प को बल मिलेगा। प्रदेश के इन स्वच्छता प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्याप्त पहचान और प्रशंसा मिल रही है। इसी वर्ष 20.21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे पर भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में किये गए प्रयासों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। इसमें मध्यप्रदेश की क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

परियोजना को तकनीकी नवाचारों की श्रेणी में प्रथम 10 प्रयास में स्थान मिला है। कचरे से बिजली बनाने वाली 6 में से 5 परियोजनाओं में तथा कचरे से खाद बनाने की 20 में से 5 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। दो अक्टूबर 2019 तक सभी परियोजनाएँ मूर्तरूप लेकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही प्रदेश के शहरों

को स्वच्छ और सुन्दर कर जनता के जीवन को और गुणवत्तापूर्ण करने में योगदान दे रही होंगी। भारत सरकार का राष्ट्र स्तरीय स्वच्छ सर्वेक्षण एक अच्छी पहल है। इसने न केवल राज्यों के मध्य स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है अपितु राज्यों को शहरीकरण की एक सकारात्मक



पहल का रास्ता भी मिला है। मध्य प्रदेश ने इस स्पर्धा में पिछले 2 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले साल के 4 शहरों और 20वें पायेदान से शुरुआत के साथ प्रदेश

है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की प्रतिस्पर्धा देश के 434 शहर के बीच थी। सर्वेक्षण 2018 में देश के समस्त 4041 शहर के मध्य यह प्रतिस्पर्धा प्रस्तावित है जिसमें 4000 अंकों के आधार पर शहरों

का मूल्यांकन किया जायेगा। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य वृहद् स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाना है।

कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन किसी एक व्यक्ति या संस्थान या किसी एक दिन का मुद्दा नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इसके लिए सबको कदम से कदम मिलाकर खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को पाना है और उसे बनाये रखना है। सर्वव्यापी स्वच्छता प्राप्त

करने के लिए सतत जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है तथा भी स्वच्छ और निर्मल मध्यप्रदेश तथा देश की संकल्पना पूरी होगी। यही संकल्पना पूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर प्रदेश और देश की उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।



इस साल देश में पहले और दूसरे स्थान पर पहुँचने में सफल रहा है। साथ ही प्रदेश के 22 शहर ने देश के पहले 100 सबसे साफ शहरों में अपनी जगह बनाई।

स्वच्छ सर्वेक्षण.2018

भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की घोषणा की गई

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य जहाँ दो इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर



मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ एक साथ दो इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गयी है। यह क्लस्टर ग्वालियर और जबलपुर में बने हैं। इनके लिए मूलभूत अधोसंरचना के विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

परियोजना के सुचारू संचालन के लिए एक पृथक कंपनी भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क लिमिटेड बनायी गयी है। क्लस्टर में 5 इकाई को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस क्षेत्र में लगभग 50 हजार रोजगार का सृजन होगा।

आई.टी. पार्क

प्रदेश के महानगर इंदौर के परदेशीपुरा एवं ग्वालियर में आई.टी. पार्क संचालित है। सिंहासा आई.टी. पार्क इंदौर, बड़वई आई.टी. पार्क भोपाल

एवं पूरवा जबलपुर में आई.टी. पार्क की स्थापना के प्रथम चरण में मूलभूत अधोसंरचना का विकास तीन चौथाई पूरा हो गया

है। आई.टी. पार्क इंदौर में 14, भोपाल में 25 एवं जबलपुर में 4 इकाई को भूमि आवंटित की गयी है।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) की स्थापना की गयी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना में मध्यप्रदेश में 400 Points of Presence (POP) केन्द्र की स्थापना की जा रही है। अब तक 380 पॉप केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 40 नई तहसील में से 20 में केन्द्रों की स्थापना की गयी।

स्टेट डेटा सेंटर

प्रदेश सरकार के सभी विभाग एवं एजेंसियों में उपलब्ध डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने एवं आपस में बाँटने की निरंतरता 365 दिन एवं 24 घंटे जारी रखने के लिये भोपाल में वर्ष 2013 से स्टेट डेटा सेंटर क्रियाशील है।

शासकीय निविदाओं में पारदर्शिता एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं के लिये वर्ष 2006 से ई-टेंडरिंग प्रणाली संचालित है। शासन के सभी विभाग/संस्थाओं के लिये e-Procurement Portal का संचालन किया जा रहा है। विभाग की सभी निविदाएँ ऑनलाइन की जाती हैं।

वर्तमान में 21 हजार 553 एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के जरिये राज्य शासन के विभिन्न विभाग द्वारा प्रदान की जा रही 450 शासकीय सेवाएँ पारदर्शी तरीके से सुविधाजनक रूप से नागरिकों को उनके निकटतम स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

आई.टी./ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण

अधिकारी/कर्मचारियों की ई-गवर्नेंस एवं आई.टी. संबंधी दक्षताओं के संवर्धन के लिये सभी 51 जिले में ई-दक्ष केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस साल सितम्बर तक लगभग 85 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को आई.टी./ई-गवर्नेंस से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

तीन पीढ़ी से आयुर्वेद चिकित्सा को
समर्पित भोपाल के स्वतंत्रता सेनानी
स्व.वैद्य उद्धवदास मेहता के पुत्र

डॉ.सौरभ मेहता, एम.डी.

आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ



डॉ.सौरभ मेहता
एम.डी.आयुर्वेद

परामर्श समय प्रातः 9:30 से 1 बजे
तक, सायं 6 बजे से 8:30 तक

**डॉ.सौरभ मेहता, हनुमान
मंदिर रोड टी.टी.नगर
भोपाल फोन: 0755-
2555309, मो. 9893963308**